पूर्ण बेंच

*एस. एस. संधावालिया से पहले सीजे, एस. सी. मित्तल, भोपिंदर सिंह ढिल्लों, एएस बैंस और हरबंस लाल, जेजे।*

न्यायालय अपने ही प्रस्ताव पर- *याचिकाकर्ता,*

*बनाम*

कस्तूरी लाल और अन्य - *उत्तरदाता। 1978* का सीआरएल।

25 मई, 1979।

*न्यायालय की अवमानना अधिनियम (1971 का एलएक्सएक्स)* - धारा *14, 15 , 17, 18* और 22 - न्यायालय की अवमानना (पंजाब और हरियाणा) नियम 1974 - *नियम* 6 (1) - *भारत का संविधान* 1950 - *अनुच्छेद* 215 और 225 - *अवमानना अधिकार क्षेत्र - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश की प्रकृति* और *दायरा*

*न्यायालय - क्या आपराधिक अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू की जा सकती है - धारा 18 - क्या ऐसी शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा है - उसमें 'सुने और निर्धारित' शब्द - क्या एक वाक्यांश के रूप में संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए* - नियम 6 (1) - *क्या अमान्य है - नियम की व्याख्या - ऐसा नियम - क्या न्यायालय द्वारा अपनी कार्रवाई पर लागू होता है।*

*यह माना जाता* है कि अंतिम विश्लेषण में, अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति न्याय के प्रशासन में किसी भी अनुचित हस्तक्षेप को रोकने और कानून की गरिमा और महिमा को बनाए रखने के व्यापक सार्वजनिक हित में है, न कि व्यक्तिगत न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए। जहां तक उच्च न्यायालयों का संबंध है, अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति उनमें न्यायालय की प्रकृति से ही निहित है। यह कहावत का प्रतीक है कि प्रत्येक न्यायालय के पास अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित शक्ति है और इंग्लैंड के सामान्य कानून द्वारा प्राचीन काल से ऐसा माना जाता रहा है। भारत की स्थिति वास्तव में अलग नहीं है। यह स्थापित कानून है कि अवमानना क्षेत्राधिकार किसी भी क़ानून का प्राणी नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड के प्रत्येक न्यायालय की एक अंतर्निहित घटना है। इसे असहमति के बिना न्यायिक रूप से माना गया था और कानूनी स्थिति अब[अनुच्छेद] 215, (पैरा 6 और 8) के आधार पर भारत के संविधान 1950 में मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठापित दोनों है।

*अदालत* की अवमानना अधिनियम, 1971 से पहले, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के पास अवमाननाकर्ता के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने और उसके लिए नोटिस जारी करने का पूर्ण अधिकार था। इतना ही नहीं, वह उस पर

निर्णय लेने और यदि आवश्यक हो तो अवमाननाकर्ता को दंडित करने का भी हकदार था। तथापि, अधिनियम में एकल न्यायाधीश द्वारा अवमानना क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर कोई पूर्ण रोक नहीं लगाई गई है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद उच्च न्यायालय के अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग सभी चरणों में और प्रत्येक मामले में दो या अधिक न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया जाना है। एकल न्यायाधीश के पास न केवल सिविल अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने की शक्ति है, बल्कि उस पर निर्णय लेने और इसके लिए दंडित करने की भी शक्ति है। फिर, धारा 14 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि जहां तक प्रथम *दृष्टया आपराधिक* अवमानना का संबंध है, विद्वान एकल न्यायाधीश न केवल कार्यवाही शुरू करने का पूर्ण हकदार है, बल्कि इसकी उप-धारा (1) (डी) के तहत, वह ऐसे व्यक्ति को दंडित करने या आरोपमुक्त करने के लिए निर्णय ले सकता है और ऐसा आदेश दे सकता है जो उचित हो। यह स्पष्ट है कि 1971 के अधिनियम के तहत भी, एकल न्यायाधीश सभी प्रकार की सिविल अवमानना के लिए और प्रथम दृष्टया किए गए आपराधिक अवमानना के लिए भी कार्रवाई करने और दंडित करने का हकदार है/इसलिए, यह इस प्रकार है कि वर्तमान अधिनियम सामान्य रूप से अवमानना अधिकार क्षेत्र के प्रयोग और विशेष रूप से उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा आपराधिक अवमानना पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाता है।

(पैरा 11 और 13)।

*धारा* 15, 17 और 18 के प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि परिणाम और प्रभाव दोनों मे धारा 18 के प्रावधान धारा 15 के तहत संज्ञान लेने के प्रारंभिक प्रयासों के बाद ही लागू होते हैं और यदि आवश्यक हो, तो धारा 17 आदि के तहत कार्यवाही शुरू करने और नोटिस की सेवा और उसमें उल्लिखित परिणामी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। इस विशेष संदर्भ में कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अंतिम सुनवाई और निर्धारण के संबंध में अधिदेश निर्धारित किया जाता है। धारा 15 के तहत आपराधिक अवमानना का केवल संज्ञान और धारा 17 के तहत अवमाननाकर्ता को दीक्षा और नोटिस स्पष्ट रूप से धारा 18 के तहत प्रदान की गई अंतिम सुनवाई और निर्धारण से अलग और संक्षेप में अलग है। जबकि धारा 15 द्वारा निर्धारित तरीकों के अनुसार संज्ञान को कम से कम एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लेने की अनुमति दी जा सकती है,

इसलिए धारा 17 में निर्धारित नोटिस जारी करने और सेवा आदि की प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं भी हो सकती हैं। यह केवल तभी होता है जब अंतिम परीक्षण के लिए मंच तैयार किया जाता है और डेस्क को सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं से मुक्त कर दिया जाता है कि धारा 18 द्वारा परिकल्पित सुनवाई और निर्धारण पहले नहीं बल्कि लागू होगा। धारा 15 को अन्य प्रावधानों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए, यह आवश्यक रूप से धारा 18 के प्रावधानों के अधीन या नियंत्रित या शासित नहीं है। उनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से समझा जाना चाहिए और धारा 15 निर्धारित तरीकों में संज्ञान लेने के प्रारंभिक चरण से संबंधित है और इसके भीतर एकल न्यायाधीश द्वारा इस शक्ति के प्रयोग के संबंध में कोई सीमा व्यक्त या निहित नहीं है और परिणामस्वरूप धारा 18 के प्रावधानों को धारा 15 में आयात करने का कोई वारंट नहीं है, यहां तक कि किसी प्रस्ताव का केवल संज्ञान लेने के पहले चरण में भी। अवज्ञा। धारा 18 में प्रयुक्त शब्द "सुना और निर्धारित" को व्यक्तिगत पृथक शब्दों के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि एक वाक्यांश के रूप में संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए। "सुनने और निर्धारित करने" वाक्यांश एक तकनीकी अर्थ पर कब्जा कर लिया गया है और जब पूर्वोक्त रंग में देखा जाता है, तो कानूनी वाक्यांश "सुना और निर्धारित" अवमानना अधिकार क्षेत्र में उठाए गए किसी भी कदम पर लागू नहीं होता है, बल्कि केवल अंतिम परीक्षण और आपराधिक अवमानना के निर्णय के लिए प्रासंगिक है। यह स्पष्ट होगा कि इस वाक्यांश की धारा 15 और 17 में निर्धारित प्रक्रिया के प्रारंभिक के लिए बहुत कम प्रासंगिकता होगी। यह केवल तभी होता है जब अवमाननाकर्ता उपस्थित हो जाता है और मामले का अंतिम निर्णय लिया जाना होता है, तब धारा 18 के प्रावधान और वाक्यांश "सुना और निर्धारित" आकर्षित होता है। केवल इसी स्तर पर विधायिका ने अपने विवेक से यह प्रावधान किया है कि इसकी सुनवाई और निर्धारण दो या अधिक न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया जाना चाहिए। इस प्रकार, यह माना जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश को आपराधिक अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने से किसी भी तरह से रोका नहीं जाता है और अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 18 इस सीमित शक्ति के प्रयोग के लिए कोई बाधा प्रस्तुत नहीं

करती है।

(पैरा 16, 19, 20 और 26) i

*चंदर कांत* वी। *टेक चंद और अन्य,* 1972 के मूल संख्या 79 पर 5 अगस्त, 1974 को फैसला किया गया। (एफ.बी.)

अति-शासित

*अदालत* की अवमानना (पंजाब और हरियाणा) नियम, 1974 के नियम 6 को अधिनियम की धारा 23 के तहत और अन्य सभी शक्तियों के तहत भी बनाया गया है, जो उच्च न्यायालय को उक्त अधिनियम के तहत अपनी कार्यवाही को विनियमित करने में सक्षम बनाता है। इसमें स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 225 के तहत संवैधानिक मंजूरी भी शामिल थी। अब यह अपनी इच्छा से है कि इस उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि आपराधिक अवमानना का संज्ञान लेने के लिए सभी प्रस्तावों, याचिकाओं या संदर्भों को कम से कम दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाना चाहिए या यदि मुख्य न्यायाधीश ऐसा निर्देश देते हैं तो बड़ी पीठ के समक्ष भी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय निर्धारित करने की अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने में पूरी तरह से अपने अधिकार क्षेत्र में है - न्यायाधीशों की संख्या के रूप में जो विशेष मामलों के मामले में कार्य करेंगे, चाहे वह एकल न्यायाधीश द्वारा हो या दो न्यायाधीशों की खंडपीठ या यहां तक कि एक बड़ी पीठ द्वारा। अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र को विनियमित करने वाले ऐसे नियम को बनाए रखा जाना चाहिए या बदला जाना चाहिए, यह पूरी तरह से उच्च न्यायालय के विवेक और नियम बनाने की शक्ति के भीतर एक मामला है। इसलिए, नियम 6 अधिनियम की धारा 23 के तहत और संविधान के अनुच्छेद 225 द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र को विनियमित करने की अंतर्निहित शक्ति के तहत उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी शक्ति का एक वैध प्रयोग होने के नाते, इस नियम की किसी भी अवैधता या अमान्यता का कोई सवाल नहीं उठता है।

(पैरा 32)

*नियम* 6(1) में प्रावधान है कि धारा 15 के तहत आपराधिक अवमानना का संज्ञान लेने के लिए प्रत्येक याचिका, प्रस्ताव या संदर्भ को कम से कम दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए। धारा 15 में उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों की आपराधिक अवमानना का संज्ञान लेने के पांच तरीकों की परिकल्पना की गई है। इनमें से एक तरीका उच्च न्यायालय के अपने प्रस्ताव पर है या जिसे उच्च न्यायालय  का गठन करने वाले एक विद्वान न्यायाधीश द्वारा

*स्वत: संज्ञान कार्रवाई* कहा जा सकता है। चीजों की प्रकृति से इस अजीब संदर्भ में, एक एकल न्यायाधीश अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या *स्वत: संज्ञान* लेते हुए कार्य करता है और स्पष्ट रूप से इस तरह की कार्रवाई को एक साथ खंडपीठ के समक्ष भी नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, *अपने स्वयं के प्रस्ताव पर न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान* कार्रवाई या कार्रवाई महाधिवक्ता या किसी निजी व्यक्ति द्वारा महाधिवक्ता की सहमति से किए गए प्रस्तावों के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायालय की आपराधिक अवमानना के संबंध में किए गए प्रस्ताव के संदर्भ से अलग प्रतीत होती है। जिस संदर्भ में इसे रखा गया है, उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि नियम 6 में प्रयुक्त शब्द "गति" चीजों की प्रकृति के अनुसार किसी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा *स्वत: संज्ञान लेते* हुए अपने दायरे में शामिल नहीं करता है और न ही कर सकता है । यह केवल न्यायालय के स्वयं के प्रस्ताव पर किए गए प्रस्तावों के अलावा प्रस्तावों को नियंत्रित कर सकता है, और परिणामस्वरूप उसके पास संज्ञान लेने और यदि आवश्यक हो तो नियम 6 (1) के मौजूदा प्रावधानों पर भी अपने स्वयं के प्रस्ताव पर आपराधिक अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्र है।

(पैरा 33)

*माननीय न्यायमूर्ति ए. एस. बैंस द्वारा 5 अक्तूबर,* 1978 *को मामले को कानून के निर्धारण के लिए एक बड़ी पीठ को सौंप दिया गया।*

*मामले में शामिल हैं। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एसएस संधावालिया और माननीय न्यायमूर्ति श्री हरबंस लाल की खंडपीठ ने* दिनांक 6 मार्च, *1979 के आदेशों के* तहत निर्णय के लिए इसे एक बड़ी पीठ को भेज दिया। *माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एसएस संधावालिया, माननीय न्यायमूर्ति एएस बैंस और माननीय न्यायमूर्ति हरबंस लाल की पूर्ण पीठ ने 21 मई, 1979 के आदेशों के माध्यम से उसी प्रश्न को अपने निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ को फिर से भेज दिया । वृहद पीठ जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मान सिंह शामिल हैं*। दक्षिणी। *एस. संधावालिया, माननीय न्यायमूर्ति एससी मित्तल, माननीय न्यायमूर्ति भोपिंदर सिंह ढिल्लों, माननीय न्यायमूर्ति एएस बैंस और माननीय न्यायमूर्ति हरबंस लाल ने* 25 मई, 1979 को प्रश्न पर निर्णय लेने के बाद धारा *18 और इस न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के* अनुसार अंतिम सुनवाई और निर्धारण के लिए मामले को खंडपीठ को लौटा *दिया: —*

*पीठ ने कहा, "क्या उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश को अदालत की अवमानना*

*अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के मद्देनजर आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से रोका जाता है?* 1971?

*माननीय न्यायमूर्ति अजीत सिंह बैंस द्वारा 1978 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 97 में प्रतिवादियों के खिलाफ पारित* दिनांक *4 सितंबर, 1978* के आदेशों के तहत न्यायालय द्वारा न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत अपने स्वयं के प्रस्ताव पर मामला उठाया *गया* ।

याचिकाकर्ता की ओर से *वरिष्ठ अधिवक्ता हरभगवान सिंह और अधिवक्ता एस. के. अहलूवालिया।*

**एक.** एस तिवाना, पंजाब राज्य के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता।

एस.सी. *हरियाणा के एडवोकेट जनरल मोहंता के साथ नौबत सिंह, सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल।*

अवमाननाकर्ताओं की ओर *से अधिवक्ता जीएस तिर और अधिवक्ता ज्ञानी बचितर सिंह।*

निर्णय

जजमेंट एसएस संधवालिया, सीजे

1. क्या उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश को न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के मद्देनजर आपराधिक अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने से रोका गया है , यह प्रश्न है, जिसे इसके महत्व और कुछ जटिलताओं के कारण निर्धारण के लिए तैयार किया गया है। पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए संदर्भ पर इस बड़ी पीठ द्वारा

2. यह थोड़ा आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि न्यायालय अवमानना अधिनियम , 1971 (इसके बाद इसे 1971 अधिनियम कहा जाएगा) के लागू होने के लगभग नौ वर्ष बीत जाने के बावजूद , उपरोक्त प्रश्न अभी भी वस्तुतः अभिन्न बना हुआ है - सिवाय इसके कि इस न्यायालय का एक निर्णय, जिसकी सत्यता स्वयं ही प्रश्न में डाल दी गई है। इसलिए, यह मामला सिद्धांत और प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के आलोक में कुछ हद तक विस्तार से विचार करने योग्य है।

3. ऐसे मामले में जो बिल्कुल कानूनी है, तथ्य स्पष्ट रूप से सापेक्ष महत्वहीन हो जाएंगे। फिर भी मुख्य प्रश्न को जन्म देने वाली इसकी मैट्रिक्स, और जिस तरीके और तरीके से यह इस बेंच के सामने आया है, उसे संक्षेप में ही सही, फिर से गिना

जाना चाहिए।

4. एक हाजी फुमन और अन्य ने इस न्यायालय में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जिसमें प्रतिवादियों को हिरासत में लिए गए लोगों को पेश करने के लिए नोटिस जारी किया गया था और आगे चलकर पुलिस स्टेशन मालेर कोटला के परिसर में उनकी तलाश करने के लिए एक वारंट अधिकारी नियुक्त किया गया था, जहां उन पर आरोप लगाया गया कि उन्हें गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है। कार्यवाही के दौरान न्यायालय द्वारा नियुक्त वारंट अधिकारी को उसके कानूनी रूप से सौंपे गए कर्तव्यों के पालन में बाधा डाली गई और जब मामला अकेले बैठे मेरे विद्वान भाई बैंस, जे. के सामने आया, तो उन्होंने नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। वर्तमान उत्तरदाताओं - एएसआई कस्तूरी लाल, एचसी दया सिंह, एचसी हरतालब सिंह, एसएचओ गुरनाम सिंह और एएसआई बचन सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना। अदालत के समक्ष पेश होने पर, उनकी ओर से तुरंत प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई कि अवमानना का यह नोटिस नहीं दिया जा सकता। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें आरोप आपराधिक अवमानना की प्रकृति के थे और यह तर्क दिया गया था कि अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के कारण, कार्यवाही की शुरुआत भी केवल एक डिवीजन बेंच द्वारा ही की जा सकती है, न कि इसके द्वारा एकल पीठ ने स्पष्ट रूप से देखा कि मौजूदा मामले में, न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना का नोटिस जारी किया गया था, बैंस, जे. ने अपने संदर्भ आदेश दिनांक 5 अक्टूबर, 1978 के माध्यम से मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा निर्धारण के लिए भेजा। डिवीजन ने हालाँकि, जिस बेंच के समक्ष मामला रखा गया था और जिसमें मैं पक्षकार था, उसने महसूस किया कि मामले में उठाया गया सार्थक मुद्दा एक आधिकारिक निर्णय का हकदार है और तदनुसार संदर्भ आदेश दिनांक द्वारा मामले को पूर्ण पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया था। 6 मार्च, 1979. इस प्रकार भारत के अटॉर्नी जनरल और दोनों राज्यों के महाधिवक्ता को भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया।

5. पूर्ण पीठ के समक्ष सुनवाई में, महत्वपूर्ण बिंदु पर एक असामान्य सर्वसम्मति थी, जहां तक कि हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता और पंजाब के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता दोनों ने यह रुख अपनाया कि एकल न्यायाधीश उच्च न्यायालय के पास कम से कम स्वत: संज्ञान लेकर अवमाननाकर्ताओं को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी करने का पूरा अधिकार क्षेत्र था और अधिनियम के प्रावधान किसी भी तरह से इस शक्ति के प्रयोग में बाधा नहीं डालेंगे। यहां तक कि प्रतिवादियों के विद्वान वकील, डॉ. टीर, जैसा कि पहले ही देखा

जा चुका है, इस रुख का विरोध करने में उदासीन थे। हालाँकि, उक्त दृष्टिकोण को स्वीकार करने में एक बड़ी बाधा 1972 के आपराधिक मूल संख्या 79 चंदर कांत बनाम टेक चंद[1] मामले में इस न्यायालय की एक असूचित पूर्ण पीठ के फैसले के रूप में देखी गई, जिसमें इसे स्पष्ट शब्दों में रखा गया था। 1971 के अधिनियम की धारा 18 के अनिवार्य प्रावधानों के मद्देनजर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के पास कार्यवाही के किसी भी चरण में मामले में जाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। यह वह कारक था जिसने पहले के दृष्टिकोण की सत्यता का परीक्षण करने के लिए वर्तमान पीठ के गठन को अनिवार्य रूप से आवश्यक बना दिया।

6. अब, हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करते समय, सबसे पहले अवमानना क्षेत्राधिकार की वास्तविक प्रकृति और दायरे को ध्यान में रखना चाहिए। अंतिम विश्लेषण में, अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति न्याय प्रशासन में किसी भी अनुचित हस्तक्षेप को रोकने और कानून की गरिमा और महिमा को बनाए रखने के व्यापक सार्वजनिक हित में है, न कि व्यक्तिगत न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए। हालाँकि, जो बात उजागर करने योग्य है वह यह है कि जहाँ तक वरिष्ठ न्यायालयों का संबंध है, अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति न्यायालय की प्रकृति से ही उनमें अंतर्निहित है। इसे इस कहावत में चरितार्थ किया गया है कि प्रत्येक अभिलेख न्यायालय के पास अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित शक्ति है। इंग्लैंड के सामान्य कानून द्वारा प्राचीन काल से ही इसे लगातार मान्यता दी गई है। वास्तव में भारत की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं है। उदाहरण की ओर ध्यान दिलाना अनावश्यक है क्योंकि व्यावहारिक रूप से भारत में प्रत्येक उच्च न्यायालय ने इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है और जब भी उसके अधिकार को चुनौती दी गई है, तो प्रत्येक ने यह माना है कि उसके पास न्यायालय की प्रकृति से ही रिकॉर्ड कोर्ट में निहित शक्ति है। यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि यह पूरे भारत में न्यायिक रूप से स्वीकार किया गया है कि यह क्षेत्राधिकार रिकॉर्ड न्यायालय की प्रकृति में निहित एक विशेष क्षेत्राधिकार है। यदि इतने स्पष्ट प्रस्ताव के लिए प्राधिकार की आवश्यकता थी, तो सुखदेव सिंह बनाम मुख्य न्यायाधीश एस. तेजा सिंह और पेप्सू उच्च [2]न्यायालय के न्यायाधीशों, एआईआर 1954 एससी 186 में अवमानना क्षेत्राधिकार पर प्रसिद्ध मामले का निर्देशात्मक रूप से संदर्भ दिया जा सकता है।

---

[1] Cr. O 79 of 1972.
[2] AIR 1954 S.C. 186.

7. न्यायिक मिसाल के अलावा, यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि इस कानूनी स्थिति की वैधानिक मान्यता सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 220 से स्पष्ट होती है, जिसके अनुसार यह घोषित किया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। यदि कोई संदेह रहता है - और वास्तव में कोई संदेह नहीं है - तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 द्वारा दूर हो जाता है जो निम्नलिखित शब्दों में इस स्थिति को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है: -

"215--उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय बनाया जाएगा--प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी जिनमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है।"

इसलिए, इस बात पर प्रकाश डाला जाना चाहिए कि अवमानना क्षेत्राधिकार का स्रोत न तो किसी अधिनियम से उत्पन्न होता है और न ही अदालत की अवमानना अधिनियम , 1971 के प्रावधानों से, बल्कि सभी रिकॉर्ड न्यायालयों की एक आवश्यक घटना है और यह लगातार होता रहा है। इसे न्यायिक मिसाल द्वारा माना जाता है और वैधानिक और संवैधानिक प्रावधानों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस पहलू पर किसी भी संदेह का समाधान 1971 के अधिनियम की धारा 22 के संदर्भ में किया जाता है, जो यह प्रावधान करता है कि इसके प्रावधान न्यायालयों की अवमानना से संबंधित किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त हैं और उनका निरादर नहीं करते हैं। यह फिर से एक तरह से रिकॉर्ड न्यायालयों द्वारा अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित शक्ति की मान्यता को दर्शाता है।

8. संक्षेप में, इस पहलू पर, यह स्थापित कानून है कि अवमानना क्षेत्राधिकार किसी क़ानून का प्राणी नहीं है, बल्कि प्रत्येक न्यायालय की एक अंतर्निहित घटना है। इसे असहमति के बिना न्यायिक रूप से ऐसा माना गया था और यह कानूनी स्थिति अब कला के आधार पर भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठापित है। 215.

9. एक बार ऐसा हो जाने पर, यह निर्धारित किया जाना बाकी रहेगा कि क्या आपराधिक अवमानना शुरू करने की शक्ति, जो कि बड़े अवमानना क्षेत्राधिकार का हिस्सा है, का प्रयोग उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है। दूसरे, यदि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में दिया जा सकता है, तो क्या सामान्य रूप से 1971 अधिनियम के प्रावधान और विशेष रूप से इसकी धारा 18 किसी भी

तरह से ऐसी शक्ति के प्रयोग में बाधा डालती है या कोई बाधा डालती है।

10. जहां तक प्रश्न के पहले अंग का संबंध है, मुझे यह मामला मिसाल के तौर पर इतना स्पष्ट रूप से कवर हुआ प्रतीत होता है कि सैद्धांतिक रूप से इसकी विस्तृत जांच करना स्पष्ट रूप से बेकार होगा। बॉम्बे राज्य बनाम "मिस्टर पी [3]" में एआईआर 1959 बीओएम 182, जो कि न्यायालय अवमानना अधिनियम 1952 के पूर्ववर्ती क़ानून के तहत दिया गया एक निर्णय है , यह प्रश्न अवमाननाकर्ता की ओर से स्पष्ट रूप से उठाया गया था। उनकी ओर से यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय की अवमानना के मामले में एकल न्यायाधीश या डिवीजन बेंच के रूप में सुनवाई नहीं हो सकती है और न्यायालय के सभी न्यायाधीश एक निकाय के रूप में एक साथ बैठकर अकेले ही उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। . इस विवाद को खारिज करते हुए, बेंच के लिए बोलते हुए, देसाई, जे. ने सबसे पहले इस प्रकार कहा:-
-

"संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले उच्च न्यायालय ने अवमानना के लिए व्यक्तियों को दंडित करने के लिए रिकॉर्ड कोर्ट के रूप में अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र और शक्ति का प्रयोग किया था और उस शक्ति का प्रयोग इस न्यायालय की स्थापना के बाद से अकेले बैठे न्यायाधीशों या डिवीजन बेंच का गठन करने वाले न्यायाधीशों द्वारा किया गया है। . जहां तक हमें जानकारी है, इस क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के एक साथ बैठने का एक भी मामला सामने नहीं आया है। संविधान के अनुच्छेद 215 में ही प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी जिनमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। अभिलेख न्यायालय के पास अवमानना के संबंध में जो शक्तियाँ हैं, वे न्यायालय के एक या अधिक न्यायाधीशों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ हैं, न कि केवल या केवल सभी द्वारा। न्यायालय के न्यायाधीश एक साथ बैठे हैं। यदि प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील का तर्क सही है, यदि न्यायालय का एक न्यायाधीश बीमारी या किसी अन्य कारण से उपलब्ध नहीं है, तो न्यायालय कार्य करने में शक्तिहीन होगा।"

इसके बाद, विद्वान न्यायाधीशों ने लेटर्स पेटेंट के प्रावधानों और न्यायालय के नियमों को समान शब्दों में निम्नानुसार निष्कर्ष निकालने के लिए विज्ञापित किया:
-

---

[3] AIR 1959 Bombay 182.

"इन प्रावधानों के मद्देनजर, उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश सशक्त है और मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का हकदार है और इसी प्रकार न्यायालय की एक खंडपीठ भी। जहां तक वर्तमान पीठ का संबंध है, इसका गठन माननीय द्वारा किया गया है मुख्य न्यायाधीश ने यहां पहले उल्लेखित प्रावधानों के तहत उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग किया। ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के मद्देनजर, भले ही इस प्रयोजन के लिए लेटर्स पेटेंट के प्रावधानों और नियमों पर भरोसा करने की कोई आवश्यकता थी। एकल न्यायाधीश या इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अवमानना के मामलों में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, हम पाते हैं कि इसके लिए पर्याप्त अधिकार हैं।"

उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने में, डिवीजन बेंच के विद्वान न्यायाधीशों ने मुरली मनोहर प्रसाद, एआईआर 1929 पैट 72 में पूर्ण पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें एक समान तर्क यह था कि एक निकाय के रूप में सभी न्यायाधीशों को बैठना आवश्यक था। अवमानना क्षेत्राधिकार के प्रयोग में एक साथ, आधिकारिक तौर पर नकारात्मक किया गया था।

11. हमसे पहले, उपरोक्त दृष्टिकोण के विपरीत एक भी प्राधिकारी का हवाला नहीं दिया गया था और न ही उसमें व्यक्त दृष्टिकोण की शुद्धता को चुनौती देने वाला कोई भी तर्क उठाया गया था। इससे सहमत होते हुए, मैं यह मानूंगा कि 1971 के अधिनियम से पहले, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के पास किसी अवमाननाकर्ता के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने और उसके लिए नोटिस जारी करने का पूरा अधिकार क्षेत्र था; इतना ही नहीं, वह उस पर निर्णय लेने और यदि आवश्यक हो तो अवमाननाकर्ता को दंडित करने का भी हकदार था।

12. एक बार जब इसे उपरोक्त मान लिया जाता है, तो विचार करने योग्य बात यह है कि क्या केवल आपराधिक अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने के सीमित उद्देश्य के लिए अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों ने किसी भी तरह से पिछली कानूनी स्थिति को बदल दिया है। अनिवार्य रूप से, यहां तर्क आवश्यक रूप से अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर आधारित होना चाहिए और संदर्भ की सुविधा के लिए, इन्हें पहले पढ़ा जा सकता है।

"15. अन्य मामलों में आपराधिक अवमानना का संज्ञान:--

(1) आपराधिक अवमानना के मामले में, धारा 14 में उल्लिखित अवमानना के अलावा , सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या --- द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर कार्रवाई कर सकता है।

(ए) महाधिवक्ता, या

(बी) महाधिवक्ता की लिखित सहमति वाला कोई अन्य व्यक्ति।

(2) अधीनस्थ न्यायालय की किसी भी अवमानना के मामले में, उच्च न्यायालय महाधिवक्ता द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर या ऐसे कानून द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए संदर्भ पर कार्रवाई कर सकता है। अधिकारी, जैसा कि केंद्र सरकार, 'आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।

(3) इस धारा के तहत किए गए प्रत्येक प्रस्ताव या संदर्भ में उस अवमानना को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसके लिए आरोपित व्यक्ति को दोषी माना जाता है।

स्पष्टीकरण--इस खंड में, अभिव्यक्ति 'महाधिवक्ता' का अर्थ है:--

(ए) सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर के संबंध में। सामान्य;

(बी) उच्च न्यायालय के संबंध में, राज्य या किसी भी राज्य के महाधिवक्ता, जिसके लिए उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है;

(सी) न्यायिक आयुक्त के न्यायालय के संबंध में, ऐसा विधि अधिकारी, जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।

16. xx xx xx xx xx

17. संज्ञान के बाद की प्रक्रिया. (1) धारा 15 के तहत प्रत्येक कार्यवाही की सूचना आरोपित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी, जब तक कि न्यायालय दर्ज किए जाने वाले कारणों से अन्यथा निर्देश न दे।

(2) नोटिस के साथ संलग्न होना होगा,--

(ए) किसी प्रस्ताव पर शुरू की गई कार्यवाही के मामले में, प्रस्ताव की एक प्रति और साथ ही शपथ पत्रों की प्रतियां, चाहे वह कोई भी हो, जिस पर ऐसा प्रस्ताव आधारित हो; और

(बी)। किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी संदर्भ पर शुरू की गई कार्यवाही के मामले में, संदर्भ की एक प्रति द्वारा।

(3) यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि धारा 15 के तहत आरोपित व्यक्ति के फरार होने या नोटिस की तामील से बचने के लिए रास्ते से बाहर रहने की संभावना है, तो वह उसकी उतनी कीमत या राशि की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे

सकता है, जितनी वह समझे। उचित।

(4) धन के भुगतान के लिए डिक्री के निष्पादन में संपत्ति की कुर्की के लिए, उप-धारा (3) के तहत प्रत्येक कुर्की सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) में प्रदान किए गए तरीके से की जाएगी, और यदि, ऐसी कुर्की के बाद जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है वह प्रकट होता है और अदालत की संतुष्टि के लिए दिखाता है कि वह नोटिस की तामील से बचने के लिए फरार नहीं हुआ या रास्ते से बाहर नहीं रहा, अदालत लागत जैसी शर्तों पर उसकी संपत्ति को कुर्की से मुक्त करने का आदेश देगी। या अन्यथा जैसा वह उचित समझे।

(5) जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है। धारा 15 के तहत अवमानना अपने बचाव के समर्थन में एक हलफनामा दायर कर सकता है, और अदालत आरोप के मामले को या तो दायर किए गए हलफनामे पर या ऐसे अतिरिक्त सबूत लेने के बाद निर्धारित कर सकती है जो आवश्यक हो और मामले के न्यायाधीश के रूप में ऐसा आदेश पारित कर सकती है। आवश्यकता है.

18. आपराधिक अवमानना के मामलों की सुनवाई न्यायपीठों द्वारा की जायेगी,--

(1) धारा 15 के तहत आपराधिक अवमानना के प्रत्येक मामले की सुनवाई और निर्धारण कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) न्यायिक आयुक्त के न्यायालय पर लागू नहीं होगी।"

13. मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रश्न पर विचार करने में हितकारी, निर्माण का सिद्धांत यह है कि किसी क़ानून के किसी भी प्रावधान को अलग से नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इसे सामंजस्यपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए और उस विशेष संदर्भ में, जिसमें यह निर्धारित किया गया है, प्रमुखता से होना चाहिए ध्यान में रखा। मुझे ऐसा लगता है कि इस फैसले पर 1971 के अधिनियम की पूरी योजना का बोझ डालना अनावश्यक है। तथापि। सबसे पहले, इस संदर्भ में जो बात उजागर करने लायक है वह यह है कि अधिनियम में ऐसा नहीं किया गया है। कोई भी रखा. एकल न्यायाधीश द्वारा अवमानना क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध। ऐसा नहीं है कि इसके बाद उच्च न्यायालय के अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग सभी चरणों में और प्रत्येक मामले में दो या दो से अधिक न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया जाएगा। यह सर्वमान्य है कि 1926 और 1952 के पहले के क़ानूनों की तरह वर्तमान अधिनियम के तहत भी, एक एकल न्यायाधीश के पास न केवल नागरिक अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने की शक्ति है, बल्कि उस पर निर्णय

देने और उसके लिए दंडित करने की भी शक्ति है। फिर से धारा 14 का संदर्भ यह स्पष्ट करता है कि जहां तक प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना का सवाल है, विद्वान एकल न्यायाधीश न केवल कार्यवाही शुरू करने का पूरी तरह से हकदार है, बल्कि उसकी उपधारा (1)(डी) के तहत भी, ऐसे व्यक्ति को दंडित करने या सेवामुक्त करने के लिए न्यायनिर्णयन और ऐसा आदेश दे सकता है जो उचित हो। संक्षेप में, यह स्पष्ट है कि 1971 के अधिनियम के तहत भी एक एकल न्यायाधीश सभी प्रकार की नागरिक अवमाननाओं के लिए पहल करने, निर्णय लेने और दंडित करने और प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमाननाओं के लिए भी हकदार है। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि वर्तमान अधिनियम उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा सामान्य रूप से अवमानना क्षेत्राधिकार और विशेष रूप से आपराधिक अवमानना के प्रयोग पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाता है।

14. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, पंजाब, श्री आईएस तिवाना ने तर्क दिया और मेरे विचार से यह सही है कि जिस क्रम में एस.एस. 1971 के अधिनियम में दिए गए 14, 15, 17 और 18 बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस संबंध में विधानमंडल के इरादे का एक पेटेंट संकेत है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना संज्ञेय है और अंततः धारा 14 के तहत अकेले बैठे विद्वान न्यायाधीश द्वारा दंडनीय भी है । हालाँकि, जहां तक अन्य प्रकार की आपराधिक अवमानना का संबंध है, उसका संज्ञान लेने का तरीका धारा 15 द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित और निर्दिष्ट किया गया है। प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना के मामलों को छोड़कर, यह धारा उच्च न्यायालय की आपराधिक अवमानना का संज्ञान लेने के तीन तरीकों की परिकल्पना करती है। ये हैं,--या तो अपनी गति पर; महाधिवक्ता द्वारा दिए गए एक प्रस्ताव पर; और, तीसरा, महाधिवक्ता की लिखित सहमति से किसी अन्य व्यक्ति के प्रस्ताव पर। जहां तक अधीनस्थ न्यायालयों की आपराधिक अवमानना का सवाल है, यह धारा फिर से संज्ञान लेने के दो और तरीके प्रदान करती है, अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए संदर्भ के माध्यम से या फिर महाधिवक्ता द्वारा किए गए उसी प्रभाव के प्रस्ताव पर। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन तरीकों का उद्देश्य अदालतों को निजी प्रतिशोध की मांग करने वाले विवादास्पद वादियों द्वारा पसंद की जाने वाली अवमानना के लिए बहुत सारी याचिकाओं से ग्रस्त होने से रोकना है। हालाँकि, जिस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह तथ्य है कि केवल धारा 15 के तहत संज्ञान और उसके तरीकों के निर्धारण से अवमाननाकर्ता के खिलाफ आपराधिक अवमानना की शुरुआत नहीं हो सकती है। वास्तव में, विद्वान एकल न्यायाधीश धारा 15 के तहत पहले चरण में भी , उसी

चरण में, अपने हाथ रोक सकता है और नोटिस जारी करने से इनकार कर सकता है। इस प्रकार कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। इसलिए अवमानना करने वाले के लिए किसी भी तरह की आपराधिक अवमानना की शुरुआत भी नहीं की जाएगी। इसलिए, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि धारा 15 के तहत किसी भी सुनवाई और निर्धारण का शायद ही कोई प्रश्न उठता है ।

15. अब प्रक्रिया, धारा 15 के तहत संज्ञान लेने के बाद , जब प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है, अधिनियम की धारा 17 द्वारा वर्णित है और जैसा कि इसके शीर्षक से संकेत मिलता है, यह प्रक्रिया प्रदान करता है संज्ञान लेने के बाद कार्यवाही शुरू की गई है। उप-धारा (1) में कहा गया है कि धारा 15 के तहत कार्यवाही की सूचना आरोपित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी और इसमें क्या शामिल होगा और उसके वैधानिक अनुबंधों के बारे में विस्तार से बताया गया है। उप-धारा (5) में प्रावधान है कि धारा 15 के तहत अवमानना का आरोप लगाया गया कोई भी व्यक्ति उप-धारा के तहत कार्यवाही के दौरान अपने बचाव के समर्थन में एक हलफनामा दाखिल कर सकता है। (3) और (4) संपत्ति की कुर्की आदि के माध्यम से उपस्थिति के लिए बाध्य करने के लिए बलपूर्वक प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि न तो धारा 15 में और न ही धारा 17 में किसी रोक या सीमा का जरा सा भी संकेत है। इस आशय का कि एक भी न्यायाधीश उन धाराओं में से किसी एक के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

16. इसके बाद सामग्री और महत्वपूर्ण धारा 18 आती है जिसमें कहा गया है कि धारा 15 के तहत आपराधिक अवमानना के प्रत्येक मामले को कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा "सुनवाई और निर्धारित" किया जाएगा और जाहिर तौर पर प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को देखते हुए, यह है निर्दिष्ट किया गया कि यह नियम न्यायिक आयुक्त के न्यायालय पर लागू नहीं होगा। अब प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि परिणाम और प्रभाव दोनों में, धारा 18 के प्रावधान धारा 15 के तहत संज्ञान लेने की प्रारंभिक प्रक्रिया के बाद ही लागू होते हैं , और यदि आवश्यक हो, कार्यवाही शुरू करने और नोटिस की सेवा के बाद ही लागू होते हैं। धारा 17 आदि के तहत और उसमें उल्लिखित परिणामी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। यह इस विशेष संदर्भ में है। इसके बाद अंतिम सुनवाई और निर्धारण के संबंध में कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा आदेश दिया जाता है। यह उपरोक्त धाराओं की पृष्ठभूमि और जिस विशिष्ट संदर्भ में उन्हें रखा गया है, उसके खिलाफ है, कि श्री तिवाना ने सार्थक तर्क उठाया था कि धारा 15 के तहत

आपराधिक अवमानना का संज्ञान और एस के तहत अवमाननाकर्ता को शुरूआत और नोटिस देना मात्र है। 17 स्पष्ट रूप से अंतिम सुनवाई और निर्धारण से भिन्न और सार रूप में अलग हैं, जो धारा 18 के तहत प्रदान किया गया है । वैधानिक प्रावधानों के बड़े स्पेक्ट्रम पर, यह सही और सशक्त रूप से तर्क दिया गया था कि धारा 15 द्वारा निर्धारित तरीकों के अनुसार संज्ञान लेते समय , कम से कम एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उठाए जाने की अनुमति दी जा सकती है, इसलिए इसकी प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं भी नोटिस आदि जारी करना और उसकी सेवा करना, धारा 17 में निर्धारित है । यह केवल तभी होता है जब अंतिम परीक्षण के लिए मंच तैयार हो जाता है और डेस्क सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं से मुक्त हो जाती है, कि धारा 18 द्वारा कल्पना की गई सुनवाई और दृढ़ संकल्प खेल में आ जाएगा और इससे पहले नहीं, मुझे इस तर्क में पेटेंट बल मिलता है, जो, मेरा विचार, स्वीकृति के योग्य है।

17. आगे बढ़ने से पहले, संभवतः अधिनियम की धारा 15 में उल्लिखित संज्ञान और अवमाननाकर्ता को नोटिस जारी करके कार्यवाही शुरू करने के बीच परिषद द्वारा बताए गए अंतर पर ध्यान देना उचित होगा। यहां मैं दंड प्रक्रिया संहिता की कई धाराओं में 'कॉग्निजेंस' शब्द के इस्तेमाल से विकसित हुई केस लॉ की नैतिकता की ओर ध्यान दिलाना अनुचित मानता हूं। यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि यहां संज्ञान शब्द का अर्थ इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सख्ती से किया जा रहा है और जैसा कि एसएस के शीर्षकों में उपयोग किया जाता है। उसके 15 और 17. अब एस. 15 . अभी तक केवल उसमें निर्धारित तरीके से आपराधिक अवमानना का संज्ञान लेने की बात की गई है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, कार्यवाही मृतप्राय साबित हो सकती है और न्यायालय आगे बढ़ना और कोई नोटिस जारी करने का निर्देश देना भी आवश्यक नहीं समझेगा। हालाँकि, आपराधिक अवमानना की शुरुआत और धारा 17 के तहत नोटिस जारी करना स्पष्ट रूप से धारा 15 के तहत संज्ञान लेने के बाद का एक चरण है जो तभी उत्पन्न होता है जब न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि नोटिस जारी करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है और आगे ऐसा करना समीचीन समझता है। नतीजतन, धारा 15 के तहत संज्ञान और धारा 17 के तहत नोटिस जारी करना, जिसे आपराधिक अवमानना की आवश्यक शुरुआत माना जा सकता है, अलग और अलग चीजें हैं। इस संबंध में अधिनियम की धारा 20 का संदर्भ दिया जा सकता है , जो सलाहपूर्वक 'आरंभ करें' शब्द का उपयोग करता है और उस तारीख से एक वर्ष की सीमा भी प्रदान करता है जिस दिन अवमानना की गई है। हालाँकि, जो बात उजागर करने लायक है, वह यह है कि ये दोनों फिर भी अंतिम

सुनवाई और दृढ़ संकल्प से एक स्पष्ट रेखा से विभाजित हैं, जिसे 1971 के अधिनियम की धारा 18 द्वारा दर्शाया गया है।

18. फिर से मामले को शायद एक और समान रूप से प्रशंसनीय और रंगीन कोण से देखा जा सकता है। इसके बाद विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के दो हालिया फैसलों का संदर्भ दिया जाएगा, जिसमें स्थापित स्थिति को दोहराया गया है कि आपराधिक अवमानना पूरी तरह से अदालत और अवमाननाकर्ता के बीच का मामला है। शिकायतकर्ता या उसके समान स्थिति वाले लोग केवल अवमानना की घटना को अदालत के ध्यान में लाने में मदद करते हैं और कार्यवाही के सख्त पक्ष में नहीं हैं, जो अवमाननाकर्ता के खिलाफ प्रतिबद्धता या सजा का सही दावा कर सकते हैं। प्रदर्शन कला की भाषा उधार लेकर कहें तो अवमानना क्षेत्राधिकार के नाटक में मुख्य कलाकार अनिवार्य रूप से न्यायालय और अवमाननाकर्ता ही होते हैं। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 18 द्वारा कल्पना की गई सुनवाई और दृढ़ संकल्प केवल तभी उत्पन्न होता है जब अवमाननाकर्ता घटनास्थल पर उपस्थित होता है और फिर न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय के लिए पर्दा उठता है। वास्तव में, धारा 18 के प्रावधान केवल नोटिस की सेवा और एसएस के तहत पहले की कार्यवाही के बाद अवमाननाकर्ता की उपस्थिति के साथ लागू होंगे। 15 और 17 केवल प्रक्रियात्मक हैं या फिर सुरम्य भाषा की ओर लौटें तो नाटक की प्रस्तावना मात्र हैं। इसलिए यह प्रशंसनीय रूप से प्रस्तुत किया गया है कि धारा 18 का धारा 15 के तहत संज्ञान लेने या धारा 17 के तहत कार्यवाही शुरू करने और नोटिस जारी करने से कोई संबंध या प्रासंगिकता नहीं है ।

19. उसी क्रम में, शिकायतकर्ता की ओर से श्री हरभगवान सिंह द्वारा यह प्रशंसनीय रूप से प्रस्तुत किया गया था कि धारा 15 को अन्य प्रावधानों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन आवश्यक रूप से नियंत्रित या शासित या एस के प्रावधानों के अधीन नहीं है। 18 . उनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से समझा जाना चाहिए और इस बात पर प्रकाश डाला गया कि यह धारा निर्धारित तरीकों में संज्ञान लेने के प्रारंभिक चरण से संबंधित है और इसके भीतर एकल न्यायाधीश द्वारा इस शक्ति के प्रयोग के संबंध में कोई स्पष्ट या निहित सीमा नहीं है। नतीजतन, यह जोरदार तर्क दिया गया कि अवमानना के प्रस्ताव का संज्ञान लेने के पहले चरण में भी धारा 18 के प्रावधानों को धारा 15 में आयात करने का कोई वारंट नहीं है। वकील ने प्रस्तुत किया कि स्वप्रेरणा से की गई कार्रवाई को छोड़कर , धारा 15 के तहत संज्ञान से आवश्यक रूप से कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती है और अदालत प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर सकती है। इन आधारों पर भी, यह सही

तर्क दिया गया कि धारा 15 के तहत इस प्रारंभिक चरण में जहां न्यायालय के पास कार्यवाही शुरू करने से इनकार करने का भी स्पष्ट विवेक है, धारा 18 के प्रावधानों को दूर से भी आकर्षित नहीं किया जा सकता है। वकील का यह तर्क सही था कि वे तभी खेल में आ सकते हैं जब मामला एसएस की प्रक्रियात्मक प्रारंभिक प्रक्रिया के बाद सुनवाई के लिए तैयार हो। 15 और 17 को पार कर लिया गया है।

20. समान रूप से मुझे हमारे सामने किए गए निवेदन में भी प्रशंसनीयता दिखती है कि "सुने" शब्द हैं। और निर्धारित" जैसा कि S, t8 में उपयोग किया जाता है, को अलग-अलग अलग-अलग शब्दों के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि एक वाक्यांश के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। यह याद रखने योग्य है कि 'सुनना' शब्द, वर्षों के बीतने के साथ एक शब्द के रूप में एक कानूनी अर्थ प्राप्त करने लगा है। कला का जब क़ानून या न्यायिक कार्यवाही में उपयोग किया जाता है। इस संबंध में संदर्भ सबसे पहले स्ट्राउड के न्यायिक शब्दकोश में दिया जा सकता है, जिसमें इसे इस प्रकार कहा गया है:

सुनो: सुनो. (1) किसी कारण या मामले को "सुनना" का अर्थ है उसे सुनना और निर्धारित करना। और "जब तक ऐसा कुछ न हो जो प्राकृतिक इरादे से, या अन्यथा, अर्थ को कम कर दे, मुझे आशंका है कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि विधायिका, जब वे किसी विशेष कारण को किसी विशेष न्यायालय में सुनने का निर्देश देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह है वहां सुना जाएगा और अंततः निपटाया जाएगा, और इसके अलावा, जब वे कहते हैं कि इसे सुना जाना है - (अर्थात, सुना जाना और अंततः निपटाया जाना) - किसी विशेष न्यायालय में, तो उनका मतलब है जब तक कि संदर्भ में कुछ ऐसा न हो जो या तो प्राकृतिक व्याख्या या आवश्यक निहितार्थ से यह कम हो जाएगा, कि उन सभी मामलों में जो उस न्यायालय के लिए प्रदान नहीं किए गए हैं, अपनी सामान्य प्रक्रिया का पालन करें" (प्रति। लॉर्ड ब्लैकबर्न। रे। ग्रीन, 51 एलजे क्यूबी 44); या, जैसा कि सेलबोर्न सी. ने इसे उसी मामले में रखा है, "सुनवाई" में न केवल इसके आवश्यक पूर्ववृत्त शामिल हैं, बल्कि इसके आवश्यक या उचित परिणाम भी शामिल हैं (उक्त 40; नामित। ग्रीन बनाम पेनज़ेंस, 6 ऐप। कैस 657)। आगे देखें आरवी कैंटरबरी (आर्कबिशप), 28 एलजे क्यूबी 154।

(2) और (3) xxx (4) जब किसी अपराध को "सुनने और निर्धारित करने" की शक्ति दी जाती है, तो शर्त निहित होती है कि आरोपी को पहले समन द्वारा उद्धृत किया जाए, और बचाव का अवसर दिया जाए (द्वार। 671, 672) .

(5) जब दो या दो से अधिक को "सुनना और निर्धारित करना" हो, तो उन्हें एक साथ बैठना चाहिए, अलग-अलग नहीं (बर्न्स जस्टिस, परिचय। xxiv, उद्धृत द्वार। 670)।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि "सुनना" शब्द के कानूनी अर्थ के अलावा "सुनना और निर्धारित करना" वाक्यांश भी प्रचलित हो गया है। एक तकनीकी अर्थ. जब उपरोक्त दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो कानूनी वाक्यांश "सुना और निर्धारित किया जाता है" को अवमानना क्षेत्राधिकार में उठाए गए हर कदम पर लागू नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसकी स्पष्ट प्रासंगिकता केवल आपराधिक अवमानना के अंतिम परीक्षण और निर्णय के लिए है। यह स्पष्ट होगा कि इस वाक्यांश की धारा 15 और 17 में निर्धारित प्रक्रिया की प्रारंभिक बातों के लिए बहुत कम प्रासंगिकता होगी । ऐसा तभी होता है जब अवमाननाकर्ता उपस्थित हुआ हो और मामले का अंतिम निर्णय किया जाना हो तब धारा 18 के प्रावधान और उसका वाक्यांश "सुना और निर्धारित किया गया" लागू होता है। यह केवल इस स्तर पर है कि विधानमंडल ने अपने विवेक से यह प्रावधान किया है कि इसे दो या दो से अधिक न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुना और निर्धारित किया जाना चाहिए। एसएस द्वारा परिकल्पित प्रारंभिक कदम। 15 और 17, जो अंतिम निर्णय के लिए मंच तैयार करते हैं, मेरे विचार में, एक डिवीजन बेंच या एक बड़ी बेंच की आवश्यकता की आवश्यकता नहीं होगी और इसलिए, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में होगा।

2एल. एक बार जब वाक्यांश "सुना और निर्धारित" को उपरोक्त अर्थ दिया जाता है, तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि धारा 15 के तहत परिकल्पित कार्यवाही और धारा 17 में निर्धारित प्रारंभिक प्रक्रिया , वास्तव में, कुछ भी तय नहीं करती है। इस पहलू में फिर से मूल अवधारणा को याद करने की आवश्यकता है कि अवमानना क्षेत्राधिकार अनिवार्य रूप से न्यायालय और अवमाननाकर्ता के बीच है, न कि प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच। जब धारा 15 के तहत एकल न्यायाधीश , मामले का संज्ञान लेने के बाद, निर्धारित किसी भी तरीके से नोटिस जारी नहीं करने का विकल्प चुनता है, तो यह दूर से नहीं कहा जा सकता है कि उसने पार्टियों के बीच कोई विवाद निर्धारित किया है। वास्तव में, इस प्रकार वह केवल उच्च न्यायालय में निहित अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार करता है। यहां तक कि जहां धारा 15 के तहत एकल न्यायाधीश संतुष्ट हो सकता है कि प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता है और नोटिस जारी करता है, ऐसा आदेश फिर से किसी भी मामले का निर्धारण नहीं है, बल्कि अभी तक केवल कार्यवाही की शुरुआत है। आरोप की सुनवाई और निर्धारण बाद में अवमाननाकर्ता की सेवा के बाद किया जाना है। यहां

तक कि धारा 17 के तहत उस चरण तक अवमाननाकर्ता को नोटिस जारी करने और उसकी तामील करने में भी किसी मामले का अंतिम कानूनी निर्धारण शामिल नहीं है। इसलिए, यह सार्थक रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धारा 15 के तहत कार्यवाही में कोई निर्धारण शामिल नहीं है और न ही धारा 17 के तहत कार्यवाही में कुछ भी तय होता है जब तक कि अवमाननाकर्ता प्रकट नहीं होता है और अपना बचाव नहीं करता है।

22. शुरुआत में ही यह देखा गया कि बेंच के समक्ष मुद्दा इस न्यायालय के एक असूचित पूर्ण बेंच के फैसले को छोड़कर पूर्ण था, जिसका विस्तृत संदर्भ इस प्रकार है। फिर भी, सादृश्य के माध्यम से, इस दृष्टिकोण के लिए कुछ मौन समर्थन, मैं लेने के लिए इच्छुक हूं, सबसे पहले उनके आधिपत्य के दो हालिया निर्णयों से प्रकट होता है; सुप्रीम कोर्ट का. बरदाकांटा में. मिश्रा बनाम गतिकृष्ण मिश्रा, उड़ीसा उच्च न्यायालय के सीजे [4], एआईआर 1974 एससी 2255। उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 15 के तहत बरदकांत मिश्रा के उदाहरण पर कोई भी कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर दिया। उक्त इनकार के खिलाफ अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील के कथित अधिकार पर इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने की मांग की गई थी। एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि चूंकि कार्यवाही शुरू करने से इनकार करने से कुछ भी निर्धारित नहीं हुआ; धारा 19 के तहत कोई अपील सक्षम नहीं थी । प्रारंभिक आपत्ति को बरकरार रखते हुए, भगवती, जे. ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए इस प्रकार कहा:--

"जहां न्यायालय स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करता है, वह अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार क्षेत्र मानता है और इसके अभ्यास में पहला कदम उठाता है। लेकिन क्या होता है जब महाधिवक्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सहमति के साथ एक प्रस्ताव दिया जाता है महाधिवक्ता का लेखन या एक संदर्भ एक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाता है? क्या न्यायालय अवमानना के लिए दंडित करने और इसके अभ्यास में कार्य करने के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करता है जब वह यह तय करने के उद्देश्य से ऐसे प्रस्ताव या संदर्भ पर विचार करता है कि क्या उसे पहल करनी चाहिए अवमानना के लिए कार्यवाही? हमें ऐसा नहीं लगता। प्रस्ताव या संदर्भ केवल कथित अवमानना की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से है और ऐसे प्रस्ताव या संदर्भ पर विचार करना न्यायालय का काम है। अपने विवेक का प्रयोग करते हुए यह निर्णय

---

[4] A.I.R. 1974 S. C. 2255.

लेना कि अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू की जाए या नहीं। न्यायालय संज्ञान लेने और अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर सकता है क्योंकि या तो उसकी राय में प्रथम दृष्टया कोई अवमानना नहीं हुई प्रतीत होती है या फिर, यहां तक कि, यदि प्रथम दृष्टया अवमानना है तो यह उपयुक्त मामला नहीं है। कथित अवमाननाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग पूरी तरह से न्यायालय और कथित अवमाननाकर्ता के बीच का मामला है, न्यायालय, हालांकि प्रस्ताव या संदर्भ द्वारा स्थानांतरित किया गया है, अपने विवेक से, अवमानना के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। यह केवल तभी होता है जब न्यायालय कार्रवाई करने का निर्णय लेता है और अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करता है, तभी वह अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार क्षेत्र मानता है। अवमानना के लिए दंडित करने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अवमानना के लिए कार्यवाही की शुरुआत के साथ शुरू होता है, चाहे वह स्वप्रेरणा से हो या किसी प्रस्ताव या संदर्भ पर हो। यही कारण है कि धारा 20 में प्रदान की गई सीमा की अवधि के लिए समाप्ति तिथि वह तारीख है जब न्यायालय द्वारा अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाती है। जहां न्यायालय किसी प्रस्ताव या संदर्भ को खारिज कर देता है और अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर देता है, तो वह अवमानना के लिए दंडित करने के अधिकार क्षेत्र को मानने या उसका प्रयोग करने से इनकार कर देता है और ऐसे निर्णय को अवमानना के लिए दंडित करने के अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में एक निर्णय के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, ऐसा निर्णय 5. 19, उप-एस के शुरुआती शब्दों के अंतर्गत नहीं आएगा। (1) और उस प्रावधान के तहत अधिकार के रूप में इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी।"

उपरोक्त टिप्पणियों और न्यायालय के अंतिम निर्णय से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अब यह आधिकारिक रूप से तय हो गया है कि धारा 15 के तहत कार्यवाही शुरू करने से इनकार करने मात्र से कुछ भी निर्धारित नहीं होता है और यह अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं है। अवमानना के लिए दंडित करने के लिए, इसलिए यह अपील योग्य नहीं है। यह अनुपात इस दृष्टिकोण को स्पष्ट समर्थन देगा कि धारा 15 के तहत कार्यवाही में धारा 18 में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई सुनवाई या निर्धारण नहीं है ।

23. इस न्यायालय का हालिया निर्णय, जो कि पुरषोतम दास गोयल बनाम

माननीय श्री न्यायमूर्ति बीएस ढिल्लों [5]एआईआर 1978 एससी 1014 में रिपोर्ट किया गया है, है। उपरोक्त दृष्टिकोण की ओर और भी अधिक सशक्त सूचक। इसमें, उच्च न्यायालय द्वारा धारा 17 के तहत अवमाननाकर्ता को नोटिस जारी करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की मांग की गई थी कि क्यों न उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अवमानना करने के लिए. फिर, एक प्रारंभिक आपत्ति ली गई कि अधिनियम की धारा 19 के तहत कोई भी अपील सक्षम नहीं थी। प्रारंभिक आपत्ति को बरकरार रखते हुए इसे इस प्रकार देखा गया:

"कार्यवाही धारा 17 के तहत एक नोटिस जारी करके शुरू की जाती है। इसके बाद, उच्च न्यायालय द्वारा उक्त कार्यवाही में कई अंतरिम आदेश पारित किए जा सकते हैं। इस न्यायालय में अपील करने का प्रावधान करना विधायिका का इरादा नहीं हो सकता है।" उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रत्येक ऐसे आदेश से अधिकार के मामले के रूप में। आदेश या निर्णय ऐसा होना चाहिए कि यह उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए विवाद के कुछ मुद्दों का फैसला करता है जो पीड़ित पक्ष के अधिकार को प्रभावित करते हैं। कार्यवाही की शुरुआत मात्र अवमानना के लिए प्रथम दृष्टया यह देखने पर कि मामला कार्यवाही तैयार करने के लिए उपयुक्त है, नोटिस जारी करने से किसी भी प्रश्न का निर्णय नहीं होता है।

xxxx .....हमारे सुविचारित निर्णय में, बिना किसी और बात के केवल कार्यवाही शुरू करने वाला आदेश कथित अवमाननाकर्ता के खिलाफ कुछ भी तय नहीं करता है और धारा 19 के तहत अधिकार के मामले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है ।

उपरोक्त से यह आवश्यक रूप से पता चलता है कि यहां तक कि जहां न्यायालय नोटिस जारी करने का निर्देश देता है और उसे धारा 17 के तहत तामील किया जाता है , उनके आधिपत्य ने राय दी है कि ऐसा है। अभी तक किसी भी मामले की सुनवाई या निर्णय नहीं हुआ है जो अपील के अधिकार को आकर्षित करेगा।

24. समान प्रभाव के लिए. और शायद जा रहा हूँ. एक कदम आगे , नरेंद्रभाई साराभाई हाथीसिंग बनाम चिनूभाई मणिभाई सेठ , एआईआर 1938 बॉम 314 में डिवीजन बेंच की टिप्पणियाँ हैं , जिन्हें बारदाकांत मिश्रा बनाम गतिकृष्ण, मिश्रा, उड़ीसा उच्च न्यायालय के सीजे, एआईआर 1974 में अनुमोदित रूप से संदर्भित किया गया है। एससी 2255 (सुप्रा)। उसमें C1 के तहत अपील. लेटर्स पेटेंट के 15 को एकल न्यायाधीश द्वारा न्यायालय को दिए गए एक वचन के उल्लंघन के लिए

[5] 1978 S.C. 1014.

प्रतिवादी को दोषी ठहराने के प्रस्ताव के नोटिस पर इनकार करने के आदेश के खिलाफ प्राथमिकता देने की मांग की गई थी। प्रारंभिक आपत्ति को बरकरार रखते हुए, कि ऐसा आदेश एक निर्णय नहीं था और किसी भी तरह से किसी अधिकार या दायित्व का निर्धारण करके पार्टियों के बीच प्रश्न की योग्यता को प्रभावित नहीं करता था, डिवीजन बेंच ने यह माना था कि ऐसे आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। लेटर्स पेटेंट के तहत. रंगनेकर, जे. ब्यूमोंट से सहमत होते हुए, सीजे ने इस प्रकार कहा:--

...अवमानना की कार्यवाही पूरी तरह से न्यायालय और उस व्यक्ति के बीच का मामला है जिस पर अवमानना का आरोप लगाया गया है। किसी भी पक्ष को यह कहने का वैधानिक अधिकार नहीं है कि वह निश्चित रूप से प्रतिबद्धता के आदेश का हकदार है क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी अवमानना का दोषी है। वह बस इतना कर सकता है कि अदालत में आए और शिकायत करे कि अदालत के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, और अगर अदालत को लगता है कि ऐसा था तो अदालत। अपने अधिकार को सिद्ध करने के लिए अपने विवेक से कार्रवाई करता है। इसलिए, यह देखना मुश्किल है कि कैसे अवमानना के लिए एक आवेदन पक्षों के बीच कोई प्रश्न उठाता है, इसलिए ऐसे आवेदन पर दिया गया कोई भी आदेश जिसके द्वारा न्यायालय अपने विवेक से गलत होने के कथित पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से इंकार कर देता है। पार्टियों के बीच कोई भी प्रश्न उठाने के लिए कहा जा सकता है। हालाँकि, सर जमशेद कांगा 25 कैल 236(3) के मामले पर भरोसा करते हैं, जहां कलकत्ता उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की राय थी कि इस अपील में हमारे जैसा आदेश अपील योग्य था। हालाँकि, इस राय के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है और विद्वान न्यायाधीशों के प्रति पूरे सम्मान के साथ, मैं इस बात से सहमत होने में असमर्थ हूँ कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में पार्टी को प्रतिबद्ध करने से इनकार करने वाला आदेश एक निर्णय है खंड 15, लेटर्स पेटेंट के अर्थ में इन परिस्थितियों में, मुझे लगता है कि प्रारंभिक आपत्ति को बरकरार रखा जाना चाहिए और अपील को लागत के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए।"

इस प्रकार उपर्युक्त टिप्पणियाँ इस प्रस्ताव के लिए पेटेंट प्राधिकारी हैं कि अवमानना के लिए प्रतिबद्ध होने से इनकार करने पर भी पार्टियों के बीच किसी भी विवाद का कोई निर्धारण शामिल नहीं होता है, और यह कोई निर्णय नहीं है।

25. इस दृष्टिकोण के लिए कुछ समर्थन कि एकल न्यायाधीश कार्यवाही शुरू

कर सकता है , सुनील कीर्ति बनाम भारत संघ और अन्य[6], एआईआर 1975 कांत 224 में एकल न्यायाधीश के फैसले में दिखाई देता है। इसमें आर. 7 जो निम्नलिखित शर्तों में है इसे धारा 18 का उल्लंघन होने के आधार पर चुनौती दी गई । और अधिनियम की धारा 19(1):--

"7. कार्यवाही की शुरुआत - अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्रवाई के लिए कोई भी याचिका, सूचना या संदर्भ, सबसे पहले, प्रशासनिक पक्ष में मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश या ऐसे अन्य न्यायाधीश या न्यायाधीश जिन्हें इस उद्देश्य के लिए उनके द्वारा नामित किया जा सकता है, अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की समीचीनता या औचित्य का निर्धारण करेंगे।"

निर्णय के विश्लेषण से पता चलता है कि यद्यपि प्रश्न स्पष्ट रूप से और अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप तर्क अपेक्षाकृत अस्पष्ट है, लेकिन इसका अनुपात यह मानने का वारंट है कि कार्यवाही की शुरुआत अकेले मुख्य न्यायाधीश द्वारा या इसके लिए अधिकृत एकल न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। आर. 7 के तहत ऐसा करना, किसी भी तरह से अधिनियम की धारा 18 या 19 के विपरीत स्पष्ट रूप से वैध अंत था।

26. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, ऐसा प्रतीत होता है कि सैद्धांतिक रूप से, क़ानून के प्रावधानों के साथ-साथ आधिकारिक उदाहरणों से समानता के माध्यम से यह माना जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश को कार्यवाही शुरू करने से किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता है। आपराधिक अवमानना के लिए और न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 18 इस सीमित शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा नहीं डालती है। इसलिए, पूर्ण पीठ के समक्ष प्रश्न का उत्तर नकारात्मक दिया गया है।

27. अब अनिवार्य रूप से मुझे चंदर कांत बनाम टेक चंद [7]में इस न्यायालय की पिछली पूर्ण पीठ के फैसले का उल्लेख करना होगा, (सीआर ओ संख्या 79/1972 5 अगस्त, 1974 को निर्णय लिया गया)। इस तथ्य में कोई दो राय नहीं है कि हमारे सामने जो प्रश्न था उसे बेंच ने निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट रूप से उठाया और नोटिस किया:--

---

[6] A.I.R. 1975, Karnataka 224.
[7] Cr. 79 of 1972 decides on 5th August, 1974.

"क्या न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 18(1) दो से कम न्यायाधीशों की पीठ को उपरोक्त संदर्भ का नोटिस जारी करने से रोकती है?

न ही इस बात पर विवाद किया जा सकता है कि खंडपीठ ने स्पष्ट शब्दों में इस आशय का उत्तर दिया कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के पास धारा 18 के अनिवार्य प्रावधानों के मद्देनजर कार्यवाही के किसी भी चरण में मामले में जाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था 1 और सभी चरणों में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही की सुनवाई कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी चाहिए।

28. हालाँकि, इस विशिष्ट बिंदु पर निर्णय का विश्लेषण स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि पक्षों के वकील मामले को उसके सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत नहीं करने में लापरवाही बरत रहे थे। मुझे अपने विद्वान भाइयों एससी मितल और ढिल्लों, जे.जे. का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस बेंच पर भी जो उक्त पूर्ण बेंच के सदस्य थे (बेंच का निर्णय स्वयं ढिल्लन, जे. द्वारा दर्ज किया गया था) और वे इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि मामला उनके सभी प्रभावों में उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिन पर ध्यान दिया गया है इस फैसले के पहले भाग में. इसलिए, सिद्धांत के साथ-साथ अधिनियम के अन्य वैधानिक प्रावधानों के संबंध में भी इस मामले पर बहुत कम चर्चा हुई प्रतीत होती है और पूरे प्रश्न को फैसले के बमुश्किल एक या दो पृष्ठों में ही निपटा दिया गया। इसमें न तो उच्च न्यायालय में निहित अवमानना क्षेत्राधिकार की वास्तविक प्रकृति का कोई संदर्भ दिखाई देता है, न ही इसकी उत्पत्ति या वर्तमान 1971 अधिनियम से पहले के विधायी इतिहास का। समान रूप से, धारा 14 , 15 , 17 और 18 का सार्थक अनुक्रम नोटिस से चूक गया और साथ ही इसकी अंतिम सुनवाई और निर्धारण से अलग अवमानना कार्यवाही के संज्ञान और शुरुआत की वास्तविक अवधारणा भी गायब हो गई। न ही धारा 18 में "सुना और निर्धारित" शब्दों के अर्थ का बिल्कुल भी विज्ञापन नहीं किया गया था। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टियों के विद्वान वकील द्वारा इस बिंदु पर कोई निर्णय उद्धृत नहीं किया गया था और किसी भी मामले में पूर्ण पीठ द्वारा इसका कोई संदर्भ नहीं दिया गया था। हालाँकि, इस बिंदु पर निर्णय में मूल त्रुटि यह धारणा है कि आपराधिक अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार क्षेत्र अधिनियम की धारा 18 द्वारा उच्च न्यायालय में निहित था, जिसके प्रावधानों को अनिवार्य माना गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस ग़लत आधार से, ऊपर बताए गए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बहस एक बिंदु पर पहुंच गई। जैसा कि शुरुआती पैराग्राफों में स्पष्ट रूप से देखा गया है। इस निर्णय के अनुसार, अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति रिकॉर्ड न्यायालय होने के नाते प्रत्येक उच्च न्यायालय में अंतर्निहित है और इसे

वैधानिक और संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। इसलिए, यह मानना ग़लत है कि 1971 अधिनियम या उस मामले के लिए किसी अन्य क़ानून ने उच्च न्यायालय को आपराधिक अवमानना के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान किया है या निहित किया है। मैं चंद्रकांत के मामले में पूर्ण पीठ की टिप्पणियों का और भी अधिक विस्तार से खंडन करना अनावश्यक समझूंगा क्योंकि मेरे दो विद्वान भाई, जो उसी पक्षकार थे (बेंच के दूसरे सदस्य नरूला, सीजे अब तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं)। अब वे स्वयं इस विचार पर हैं कि यह कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है। तदनुसार, मैं इस विशिष्ट बिंदु पर 5 अगस्त, 1974 को निर्णय किए गए चंद्रकांत बनाम टेक चंद, क्रि मूल संख्या 79, 1972 को खारिज कर दूंगा।

29. हालांकि, इस फैसले से अलग होने से पहले, मैं यह नोटिस करना जरूरी समझता हूं कि अधिनियम की धारा 18 द्वारा कथित तौर पर पेश की गई पत्थर की दीवार को पार करने के बाद भी, नियम 6 द्वारा रास्ते में एक छोटी सी बाधा खड़ी करने की कोशिश की गई थी। न्यायालय की अवमानना (पंजाब और हरियाणा) नियम 1974 , न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 23 के तहत न्यायालय द्वारा स्वयं बनाए गए हैं। नियम 6 के प्रासंगिक भाग निम्नलिखित शर्तों में हैं: -

"6: (1) आपराधिक अवमानना के संबंध में प्रत्येक याचिका, प्रस्ताव या संदर्भ, जब तक कि मुख्य न्यायाधीश इसे एक बड़ी पीठ द्वारा सुनवाई का निर्देश नहीं देते, कम से कम दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखी जाएगी।

(2) सिविल अवमानना के संबंध में प्रत्येक याचिका, प्रस्ताव या संदर्भ, जब तक कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए, एकल पीठ के समक्ष रखी जाएगी।

(3) उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक नोटिस इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र में होगा और उसके साथ प्रस्ताव, याचिका या संदर्भ की एक प्रति, जैसा भी मामला हो, शपथ पत्र की प्रतियों के साथ, यदि कोई हो, संलग्न होगी।

हम उपरोक्त उप-नियम (1) से सीधे तौर पर चिंतित हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हुआ कि यह प्रावधान या तो किसी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया में बाधा है या वैकल्पिक रूप से, यह अच्छी तरह से हो सकता है। यह अधिनियम का ही उल्लंघन है, और इसलिए इसके दायरे से बाहर है। हालाँकि, गहराई से बारीकी से विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि दोनों में से कोई भी स्थिति सत्य नहीं है।

30. संविधान के लागू होने से पहले भी सभी उच्च न्यायालयों के पास नियम बनाकर अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को विनियमित करने की शक्ति थी, यह वास्तव में बहुत ही स्वयंसिद्ध है और इसलिए किसी बड़े विस्तार की आवश्यकता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस शक्ति की वैधानिक मान्यता भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 108 में ही कर दी गई है, जो इस प्रकार है:--

"प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने स्वयं के नियमों के अनुसार, एक या अधिक न्यायाधीशों द्वारा, या उच्च न्यायालय के दो या अधिक न्यायाधीशों द्वारा गठित डिवीजन अदालतों द्वारा, न्यायालय में निहित मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अभ्यास के लिए उचित समझे जाने पर प्रावधान कर सकता है। "

31. इस संदर्भ में इस तथ्य के अलावा और कुछ भी नोटिस करना अनावश्यक लगता है कि संविधान के अनुच्छेद 225 ने इस शक्ति को दूसरों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों में संरक्षित किया है:--

"225। इस संविधान के प्रावधानों और उपयुक्त किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन। इस संविधान द्वारा उस विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बनाया गया विधानमंडल, किसी भी मौजूदा उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र और प्रशासित कानून और न्यायालय में न्याय के प्रशासन के संबंध में उसके न्यायाधीशों की संबंधित शक्तियां, जिसमें न्यायालय के नियम बनाने और न्यायालय की बैठकों और अकेले या डिवीजन न्यायालयों में बैठे सदस्यों को विनियमित करने की कोई भी शक्ति शामिल है, वही होंगी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले की तरह।"

यह मुद्दा स्वयं क़ानून के स्पष्ट प्रावधानों से स्पष्ट प्रतीत होता है, लेकिन यदि किसी प्राधिकार की आवश्यकता थी तो वह नेशनल सिलाई थ्रेड कंपनी लिमिटेड, चिदंबरम बनाम जेम्स चैडविक और ब्रदर्स [8]की बाध्यकारी मिसाल में उपलब्ध है । लिमिटेड, एआईआर 1953 एससी 357, जिसमें यह निम्नानुसार देखा गया है:--

"...हमारी राय में यह आपत्ति भी सही नहीं है क्योंकि यह इस तथ्य को नजरअंदाज करती है कि धारा 108 द्वारा उच्च न्यायालय को जो शक्ति प्रदान की गई थी वह अभी भी कायम है, और यह सरकार द्वारा किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुई है भारत अधिनियम 1935 या नए संविधान द्वारा। दूसरी ओर इसे जीवित रखा गया है और इन क़ानूनों द्वारा बड़ी ताकत के साथ इसकी पुष्टि की गई है, उच्च न्यायालयों को अभी भी वही निरंकुश शक्ति प्राप्त है जो उन्हें भारत सरकार

[8] A.I.R. 1953 S.C. 357.

अधिनियम की धारा 108 के तहत प्राप्त थी, 1915 नियम बनाने और यह प्रावधान करने के लिए कि क्या किसी अपील की सुनवाई एक न्यायाधीश या अधिक न्यायाधीशों द्वारा या उच्च न्यायालय के दो या अधिक न्यायाधीशों वाले डिवीजन न्यायालयों द्वारा की जानी है।

यह महत्वहीन है कि किस लेबल या नामकरण से उस शक्ति का वर्णन विभिन्न क़ानूनों या लेटर्स पेटेंट में किया गया है। शक्ति वहाँ है और बनी रहेगी और इसका प्रयोग उसी तरीके से किया जा सकता है जैसे इसका प्रयोग तब किया जा सकता था जब इसे मूल रूप से प्रदान किया गया था। इतिहास की बात करें तो यह शक्ति पहली बार धारा 108 , भारत सरकार अधिनियम, 1915 द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। यह पहले ही 1861 की धारा 13 भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम द्वारा प्रदान की जा चुकी थी।"

फिर फरजंद बनाम मोहन सिंह [9]एआईआर 1968 सभी 67 में, सतीश चंद्र, जे. (जैसा कि उस समय उनका आधिपत्य था) ने आगे कहा है कि न्यायिक पक्ष के अलावा, यहां तक कि प्रशासनिक पक्ष पर भी उच्च न्यायालय को विनियमित करने और निर्धारित करने का समान अधिकार है। क्या कुछ मामलों पर पूरे न्यायालय द्वारा या न्यायाधीशों की समिति द्वारा, या यहाँ तक कि एक न्यायाधीश द्वारा विचार किया जाना है

32. अब उपरोक्त नियम 6 को न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 23 के तहत और उच्च न्यायालय को उक्त अधिनियम के तहत अपनी कार्यवाही को विनियमित करने में सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों के तहत तैयार किया गया है । इसमें स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 225 के तहत संवैधानिक मंजूरी समान रूप से शामिल है। अब यह अपनी इच्छा से है कि इस उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि संज्ञान लेने या आपराधिक अवमानना के लिए सभी गतियों, याचिकाओं या संदर्भों को एक डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाना है। कम से कम दो न्यायाधीश या यदि मुख्य न्यायाधीश एक बड़ी पीठ के समक्ष भी ऐसा निर्देश देते हैं तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मामले में कार्य करने वाले न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने में उच्च न्यायालय पूरी तरह से अपने अधिकार क्षेत्र में है। विशेष कार्यवाही चाहे वह एकल न्यायाधीशों या दो न्यायाधीशों की खंडपीठ या यहां तक कि एक बड़ी पीठ द्वारा हो। क्या अपने अधिकार क्षेत्र को विनियमित करने वाले ऐसे नियम को

---

[9] A.I.R. 1968 Allahabad 67.

बरकरार रखा जाना चाहिए या बदला जाना चाहिए, यह पूरी तरह से विवेक और नियम-निर्धारण का मामला है। उच्च न्यायालय की शक्ति. इसलिए, नियम 6, अधिनियम की धारा 23 के तहत और अपने स्वयं के क्षेत्राधिकार को विनियमित करने की अंतर्निहित शक्ति के तहत, कला द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त , उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी शक्ति का एक वैध अभ्यास है। संविधान के 225 के अनुसार, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में इस नियम की किसी भी अवैधता या अमान्यता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

33. हालाँकि, नियम 6 के उप-नियम (1) के आवेदन के संबंध में व्याख्या का मामला फिर भी विचार के लिए उठता है। इसमें प्रावधान है कि धारा 15 के तहत आपराधिक अवमानना का संज्ञान लेने के लिए प्रत्येक याचिका, प्रस्ताव या संदर्भ को कम से कम दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए। जैसा कि पहले देखा गया है, धारा 15 में स्वयं उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ अदालतों की आपराधिक अवमानना का संज्ञान लेने के पांच तरीकों की परिकल्पना की गई है। इनमें से एक तरीका उच्च न्यायालय के स्वयं के प्रस्ताव पर है या जिसे उच्च न्यायालय का गठन करने वाले एक विद्वान न्यायाधीश द्वारा स्वत: संज्ञान कार्रवाई कहा जा सकता है। चीजों की प्रकृति से इस अजीब संदर्भ में, एक एकल न्यायाधीश अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या स्वत: प्रेरणा से कार्य करता है और जाहिर तौर पर ऐसी कार्रवाई को एक साथ डिवीजन बेंच के समक्ष भी नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, स्वप्रेरणा से की गई कार्रवाई या सटीक कहें तो न्यायालय द्वारा अपने स्वयं के प्रस्ताव पर क़ानूनी कार्रवाई द्वारा लागू की गई शब्दावली का उपयोग करना, मुझे महाधिवक्ता या किसी निजी व्यक्ति की सहमति से किए गए प्रस्तावों से अलग और अलग प्रतीत होता है। महाधिवक्ता के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायालय की आपराधिक अवमानना के संबंध में दिए गए प्रस्ताव का संदर्भ भी। जिस संदर्भ में इसे रखा गया है, यह स्वतः स्पष्ट प्रतीत होता है कि नियम 6 में प्रयुक्त शब्द "मोशन" चीजों की प्रकृति के कारण, किसी एकल न्यायाधीश द्वारा स्वत: संज्ञान वाली कार्रवाई को अपने दायरे में शामिल नहीं करता है और न ही कर सकता है। यह न्यायालय के स्वयं के प्रस्ताव के अलावा केवल अन्य प्रस्तावों को ही नियंत्रित कर सकता है। यह निर्माण, मेरे विचार में, एकमात्र उचित है जिसे आर. 6, (खंड 1) के प्रावधानों पर सामंजस्यपूर्ण रूप से रखा जा सकता है। उसे इस व्याख्या में कोई विसंगति नहीं दिखती और यदि कोई विसंगति होती भी है, तो यह याद रखने योग्य है कि व्याख्या का हितकर सिद्धांत यह है कि, यदि दो निर्माण संभव हैं, तो एक वैधता और संवैधानिकता के अनुरूप हो। प्रावधान का, और दूसरा इसके विरुद्ध,

तो पहले वाले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसलिए, मेरा मानना है कि आर: 6(1) किसी भी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वत: संज्ञान कार्रवाई के लिए आकर्षित नहीं है और परिणामस्वरूप उसके पास संज्ञान लेने और यदि आवश्यक हो, तो आपराधिक अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने का पूरा अधिकार क्षेत्र है। प्रस्ताव, यहां तक कि नियम 6(1) के मौजूदा प्रावधान भी।

34. जैसा कि ऊपर दिया गया है, महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया गया है, इसका एक आवश्यक परिणाम यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपने स्वयं के प्रस्ताव पर उत्तरदाताओं के खिलाफ जारी किया गया आपराधिक अवमानना का नोटिस पूर्ण वैधता वाला है। उत्तरदाताओं को विधिवत सेवा देने और उपस्थित होने के बाद, मामले को धारा 18 और इस न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष अंतिम सुनवाई और निर्धारण के लिए रखने का निर्देश दिया जाता है।

एससी मितल, जे.

35. मैं सहमत हूं.

भोपिंदर सिंह ढिल्लों, जे.

36. मैं सहमत हूं.

एएस बैंस, जे.

37. मैं सहमत हूं.

हरबंस लाल, जे.

38. मैं सहमत हूं.

39. प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी

व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

श्रेया बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा